

बंगाल में यूसीसी पर बड़ा कदम



► **समीक्षा करने के लिए 9 सदस्यीय समिति गठित**

► **बंगाल में यूसीसी बिल को अंतिम रूप देने की तैयारी**

कोलकाता, 11 जुलाई. **पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य में प्रस्तावित समान नागरिक संहिता (यूसीसी) 2026 के मसौदे की समीक्षा और परीक्षण के लिए नौ सदस्यीय विशेषज्ञ समिति का गठन किया है।**

सुप्रीम कोर्ट की सेवानिवृत्त न्यायाधीश जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई को समिति का अध्यक्ष बनाया गया है. राज्य सरकार की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार समिति विधानसभा में विधेयक पेश किए जाने से पहले ड्राफ्ट बिल की व्यापक जांच कर अपनी सिफारिशें देगी. सरकार को उम्मीद है कि प्रस्तावित

विधेयक विधानसभा के अगस्त सत्र में प्रस्तुत किया जा सकता है. अधिसूचना में कहा गया है कि विषय के व्यापक प्रभाव और इसके विभिन्न कानूनी एवं सामाजिक पहलुओं को देखते हुए ड्राफ्ट बिल की विस्तृत समीक्षा आवश्यक है. इसी उद्देश्य से राज्यपाल की स्वीकृति के बाद विशेषज्ञ समिति का गठन तत्काल प्रभाव से किया गया है. प्रस्तावित कानून का उद्देश्य राज्य के सभी नागरिकों के लिए विवाह, तलाक, उत्तराधिकार, विरासत और गोद लेने जैसे व्यक्तिगत नागरिक मामलों के एक समान कानूनी व्यवस्था उपलब्ध कराना है, चाहे

रंजना देसाई करेंगी अगुवाई

समिति में जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई के अलावा मेघालय के पूर्व राज्यपाल तथागत रॉय, आईएस अधिकारी दूयत नरियाला, सेवानिवृत्त आईएस अधिकारी शत्रुघ्न सिंह, प्रमुख सचिव संघमित्रा घोष, मानव विज्ञान की पूर्व प्रोफेसर डॉ. रत्ना भट्टाचार्य, गौर बंग विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति गोपालचंद्र मिश्रा, कलकत्ता हाईकोर्ट के अधिका उस्मान गनी भट्टिक तथा पूर्व कार्यकारी निदेशक निर्मल्य भट्टाचार्य को सदस्य बनाया गया है.

उनका धर्म, आस्था या समुदाय कोई भी हो. सरकार ने स्पष्ट किया है कि प्रस्तावित कानून में आदिवासी समुदायों सहित उन श्रेणियों को संवैधानिक प्रावधानों

बिना मुकदमा 1 साल तक हिरासत

पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य में कानून-व्यवस्था को और सख्त बनाने के उद्देश्य से दो नए कानून लागू करने का फैसला किया है. राज्यपाल की मंजूरी मिलने के बाद लागू किया गया है. नए कानून के तहत ऐसे लोगों की पहचान की जाएगी, जिन्हें समाज विरोधी या गुंडा गतिविधियों में शामिल माना जाएगा. ऐसे मामलों में आरोपियों को बिना मुकदमा चलाए अधिकतम 12 महीने तक हिरासत में रखा जा सकेगा.

के अनुरूप छूट देने का प्रस्ताव रखा गया है.



वैशाली में मंची अफरातफरी

हेलीकॉप्टर के सामान्य समय से अधिक देर तक हवा में बने रहने और कुछ पल के लिए नीचे आने जैसी स्थिति बनने से कार्यक्रम स्थल पर प्रशासनिक अधिकारियों व सुरक्षाकर्मियों की चिंता बढ़ गई. हालांकि कुछ मिनट बाद हेलीकॉप्टर ने दोबारा

सुरक्षा एजेंसियां तुरंत अलर्ट मोड में आ गईं और अक्षयवद राय स्टेडियम में तैनात पुलिसकर्मियों ने पहचानात्मक लोगों को मैदान से हटाना शुरू कर दिया. मौके पर मौजूद कई पत्रकार और कार्यकर्ता भी भ्रमवित्त खतरे की आशंका से सुरक्षित स्थानों की ओर जाने लगे, जिससे कुछ देर के लिए अफरातफरी का माहौल बन गया.

संतुलन बनाया और सुरक्षित रूप से पटना के लिए रवाना हो गया. घटना के कारणों को लेकर अभी तक कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है. प्रारंभिक तौर पर तकनीकी खराबी की आशंका जताई जा रही है. प्रशासन की ओर से भी हेलीकॉप्टर के हवा में अधिक देर तक मंडराने की वजह स्पष्ट नहीं की गई है.



ज्ञान प्रकाश मणिपुर लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष नियुक्त

इम्फाल. एच ज्ञान प्रकाश को मणिपुर लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है. कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग (कार्मिक प्रभाग) की ओर से शुक्रवार को जारी आदेश के अनुसार श्री ज्ञान प्रकाश पद संभालने की तारीख से छह साल की अवधि के लिए या 62 वर्ष की आयु पूरी होने तक, जो भी पहले हो, अध्यक्ष के रूप में काम करेंगे. उनका वेतन, भत्ते और सेवा की अन्य शर्तें समय-समय पर संशोधित मणिपुर लोक सेवा आयोग नियामक-1972 के अनुसार तय होंगी.

शिवराज देशभर के वृक्ष मित्रों से करेंगे संवाद

नई दिल्ली. केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान रविवार को यहां पूसा परिसर में आयोजित पर्यावरण संरक्षण संकल्प कार्यक्रम में देश भर के लगभग 17 हजार वृक्ष मित्रों से संवाद कर पर्यावरण संरक्षण को जनभागीदारी का सशक्त अभियान बनाने का आह्वान करेंगे और पर्यावरण संरक्षण के जनआंदोलन को नई ऊर्जा देंगे. यहां जारी एक आधिकारिक विज्ञप्ति में बताया गया है कि इस कार्यक्रम में पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र से जुड़ी देश की प्रतिष्ठित हस्तियां एवं 500 से अधिक वृक्ष मित्र प्रत्यक्ष रूप से शामिल होंगे, जबकि 16 हजार से अधिक प्रतिभागी इंटरनेट के माध्यम से दूर बैठकर इस कार्यक्रम से जुड़ेंगे. कार्यक्रम में देश के सुप्रसिद्ध पर्यावरणविद अनिल जोशी और अनूप हजेला भी शामिल होंगे.

डॉन बाबा फरजान के काले साम्राज्य का खुलासा

► **तहखाने से 5 करोड़ कैश सोना और हथियारों का जखीरा बरामद**

संभाजीनगर, 11 जुलाई. महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजी नगर में 90 के दशक के कथित अंडरवर्ल्ड डॉन बाबा फ़रज़ान के आलीशान बंगले पर हुई क्राइम ब्रांच की छापेमारी की गई है.

पुलिस ने बंगले के गुप्त हिस्सों और तहखाने की तलाशी के दौरान करीब 5 करोड़ नकद, 21 लाख के सोने के आभूषण, 8 लाख की चांदी चार राइफलें, 500 जिंदा कारतूस, तलवारें और कई धारदार हथियार बरामद करने का दावा किया है. नकदी इतनी ज्यादा थी



कि उसकी गिनती के लिए मौके पर नोट गिन्ने की मशीनें मंगानी पड़ीं. इसके साथ ही संपत्ति और वित्तीय लेन-देन से जुड़े कई अहम दस्तावेज भी पुलिस के हाथ लगे हैं. खास बात यह है कि बाबा फ़रज़ान की मौत के कुछ समय बाद हुई इस कार्रवाई ने उनके कथित आपराधिक नेटवर्क और अवैध संपत्तियों को लेकर नए

सवाल खड़े कर दिए हैं. पुलिस अब बरामद दस्तावेजों और हथियारों के आधार पर पुराने नेटवर्क, आर्थिक लेन-देन और संभावित सहयोगियों की जांच में जुटी है. इस हाई-प्रोफाइल रेड के बाद एक कार फिर 90 के दशक के उस डॉन का नाम सुर्खियों में है, जिसका कभी संभाजीनगर में दबदबा और खौफ माना जाता था.

भ्रष्टाचार का पर्याय बन चुका है मध्य प्रदेश : मल्लिकार्जुन खरगे

नई दिल्ली, 11 जुलाई. कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने मध्यप्रदेश भाजपा सरकार के शासन में भ्रष्टाचार और लूटपाट होने का बड़ा आरोप लागते हुए कहा है कि राज्य आज भ्रष्टाचार का केंद्र बन गया है तथा एक के बाद एक घोटाले सामने आ रहे हैं. श्री खरगे ने शनिवार को सोशल मीडिया एक्स पर पर एक पोस्ट में कहा कि अब एथेनॉल के नाम पर 1,200 करोड़ रुपये के चावल घोटाले का मामला सामने आया है. राज्य में कुपोषित बच्चों, गर्भवती महिलाओं और किशोरियों के पोषण के लिए निर्धारित करीब पांच लाख टन चावल को राइस मिलरों, एथेनॉल कारोबारियों और सरकारी संरक्षण में कथित भ्रष्टाचार का हिस्सा बनाया गया. उन्होंने कहा कि इससे पहले उज्जैन में जमीनों से जुड़ा बड़ा घोटाला सामने आया था, जहां कथित तौर पर उन्हीं क्षेत्रों में



जमीनों का विस्तार हुआ, जहां सरकारी अवसंरचना परियोजनाएं और हाईवे कॉरिडोर प्रस्तावित थे. राज्य सरकार की भूमिका इस मामले में सवालों के घेरे में है कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि व्यापम घोटाले से शुरू हुई भ्रष्टाचार की यह शृंखला आज तक नहीं थमी है और पेपर लीक सहित अनेक मामलों ने प्रदेश को छवि को प्रभावित किया है. उन्होंने कहा कि भाजपा ने मध्यप्रदेश को भ्रष्टाचार का मॉडल बना दिया है तथा प्रधानमंत्री की चुप्पी जवाबदेही पर गंभीर सवाल खड़े करती है.

आज का इतिहास

1290 - इंग्लैंड के सम्राट एडवर्ड प्रथम के आदेश पर यहूदियों को बाहर निकाला गया.

1909 - हिन्दी फिल्मों के एक महान् फिल्म निर्देशक बिमल राय का जन्म.

1912 - कीन एलिजाबेथ अमेरिका में प्रदर्शित होने वाली पहली विदेशी फिल्म बनी

1918 - टोकायाम की खाड़ी में जापानी युद्धपोत में विस्फोट में 500 लोगों की मौत.

1960 - भागलपुर और रांची यूनिवर्सिटी की स्थापना.

1970 - अलकनंदा नदी में आई भीषण बाढ़ ने 600 लोगों की जान ली।

1972 - भारतीय मूल के अमेरिकी नागरिक एवं गुगल खोज अनुभाग के सीईओ सुंदर पिचाई का जन्म.

हस्तियों के द्वाीट



टेस्ला के सीईओ एलन मस्क हाल ही में सोशल मिडिया एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि हमेशा की तरह, पुराने मीडिया ने स्थिति को गलत तरीके से पेश किया है. मैंने बस टेस्ला और स्पेसएक्स से ग्रीक 4.5 को आजमाने के लिए कहा था ताकि यह देखा जा सके कि क्या यह उनके काम को पूरा करता है, न कि यह कि वे हर हाल में इसका इस्तेमाल करें.



इटली की प्रधानमंत्री जोर्जिया मेलोनी ने हाल ही में सोशल मिडिया एक्स पर एक पोस्ट साझा करते हुए लिखा कि अपनी और इटली सरकार की ओर से, मैं अंडालूशिया में लगी दुखद आग के पीड़ितों के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करती हूँ. हमारी संवेदनाएँ उन लोगों के परिवारों के साथ हैं जो लापता हो गए हैं और उन सभी के साथ जो इस गंभीर आपातकालीन स्थिति से प्रभावित हुए हैं.

सेना पराक्रम स्वदेशी युद्धोपेत महेंद्रगिरि भारतीय नौसेना में शामिल

हिन्द महासागर में बढ़ेगी भारत की ताकत



विशाखापत्तनम,11 जुलाई. अत्याधुनिक स्वदेशी स्टील्थ युद्धपोत आईएनएस महेंद्रगिरि शनिवार को यहां में एक समारोह में नौसेना के बेड़े में शामिल हो गया. रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इसे ऐतिहासिक अवसर और इस अग्रिम पंक्ति के युद्धपोत को भारत की जहाज निर्माण में बढ़ती आत्मनिर्भरता का प्रतीक बताया.

पिछले डेढ़ वर्ष में नौसेना में शामिल होने वाला यह प्रोजेक्ट 17 ए का छठा स्वदेशी युद्ध पोत है. इसमें 75 प्रतिशत से अधिक स्वदेशी सामग्री का उपयोग किया गया है. इसका

डिजाइन भारतीय नौसेना के वॉरशिप डिजाइन ब्यूरो ने तैयार किया है और इसका निर्माण मुंबई स्थित मझगांव डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड ने किया है. समारोह को संबोधित करते हुए श्री सिंह ने कहा कि आईएनएस महेंद्रगिरि तकनीकी रूप से उन्नत और युद्ध के लिए तैयार नौसेना के निर्माण के प्रति देश की प्रतिबद्धता का प्रतीक है. उन्होंने कहा कि समुद्री और आर्थिक सुरक्षा एक-दूसरे से जुड़ी हुई हैं. उन्होंने भारत के सागर दृष्टिकोण के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता दोहरायी और कहा कि मानवीय सहायता, समुद्री

नौसेना प्रमुख एडमिरल कृष्ण मोहनन ने कहा कि आईएनएस महेंद्रगिरि का शामिल होना स्वदेशी युद्धोपेत निर्माण की दिशा में एक और महत्वपूर्ण उपलब्धि है, जिससे नौसेना की परिवारगत क्षमता में अंशेखनीय वृद्धि होगी. उन्होंने कहा कि प्रोजेक्ट 17ए के तहत शुभारंभ से डिलीवरी तक का समय 63 महीने से घटकर 31 महीने और कुल निर्माण अवधि 95 महीने से घटकर 75 महीने कर दी गयी है. जबकि सभी तकनीकी परीक्षणों केवल एक समुद्री परीक्षण में पूरे किये गये.

डैकेटी रोधी अभियानों तथा ऑपरेशन ऊर्जा सुरक्षा में नौसेना की भूमिका भारत के आर्थिक हितों की रक्षा में उसके योगदान को दर्शाती है।

असम में मादक पदार्थ मामले में गिरफ्तार राइफलमैन निलंबित

अगरतला. त्रिपुरा स्टेट राइफल्स (टीएसआर) के एक जवान को असम में नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेन्स (एनडीपीएस) अधिनियम के तहत दर्ज मामले में गिरफ्तार किये जाने के बाद निलंबित कर दिया गया है. अधिकारियों ने शनिवार को यह जानकारी दी. आधिकारिक निलंबन आदेश के अनुसार, टीएसआर की तेरहवीं बटालियन के खुफिया शाखा में तैनात राताबाड़ी थाने में नौ जुलाई को एनडीपीएस अधिनियम की धारा 22(सी), 25 और 29 के तहत दर्ज मामले में गिरफ्तार किया गया था. तेरहवीं बटालियन के कमांडेंट ने केंद्रीय सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं आपीत) नियम, 1965 के नियम 10(2) के तहत

रियांग को नौ जुलाई से प्रभावी माने जाने वाले आदेश के साथ निलंबित कर दिया है. यह निलंबन आगले आदेश तक प्रभावी रहेगा. निलंबन आदेश में कहा गया है कि न्यायिक हिरासत से रिहा होने के बाद सचिंद्र रियांग को तेरहवीं बटालियन टीएसआर मुख्यालय में रिपोर्ट करना होगा और कमांडेंट की पूर्व अनुमति के बिना मुख्यालय नहीं छोड़ सकेगे. सूत्रों के अनुसार, गिरफ्तारी के समय रियांग बटालियन की खुफिया शाखा में तैनात बल के एक जवान की कथित सौलसता के कारण यह मामला विशेष रूप से चर्चा में है. असम पुलिस एनडीपीएस मामले की जांच कर रही है, जबकि निलंबित टीएसआर जवान के विरुद्ध विभागीय कार्रवाई भी सेवा नियमों के अनुसार आगे बढ़ाई जाएगी.

टिकाऊ परिवहन के लिए बढ़े साझेदारी

► **ब्रिक्स मंच से गडकरी ने किया आह्वान**

नई दिल्ली, 11 जुलाई. सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने ब्रिक्स समूह में टिकाऊ, सुरक्षित, समावेशी और भविष्य की जरूरतों के अनुरूप परिवहन व्यवस्था विकसित करने के लिए परस्पर सहयोग बढ़ाने की जरूरत पर बल देते हुए सभी देशों से मिलकर काम करने का आह्वान किया है.

श्री गडकरी ने नागपुर ब्रिक्स देशों के परिवहन मंत्रियों की तीसरी बैठक का उद्घाटन करते हुए शनिवार को कहा कि बैठक में विचार के लिए परिवहन व्यवस्था



का जो एजेंडा तैयार किया है, वह महत्वपूर्ण है क्योंकि बदलती अर्थव्यवस्थाओं के लिए परिवहन भविष्य की सबसे बड़ी चुनौती है और इस चुनौती पर समूह के सभी देशों का मिलकर ध्यान देना आवश्यक हो गया है। उन्होंने कहा कि उपरती अर्थव्यवस्थाओं के बीच परिवहन क्षेत्र में सहयोग से काम करने की जरूरत है क्योंकि ब्रिक्स देशों में अर्थव्यवस्थाएं तेजी से बदल रही हैं.

एआई विकसित भारत 2047 का मंत्र

► **आईटी उद्योग को अश्विनी वैष्णव की बड़ी सलाह**

► **एआई बनेगा सबसे बड़ा हथियार**



नई दिल्ली, 11 जुलाई. 'विकसित भारत 2047' के लक्ष्य को हासिल करने में कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) की अहम भूमिका होगी. केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने हैदराबाद में आयोजित एक संगोष्ठी में कहा कि एआई का दौर पूरी दुनिया के आईटी उद्योग को तेजी से बदल रहा है.

ऐसे में भारत को इस बदलाव का पूरा लाभ उठाते हुए नवाचार,

अनुसंधान और नई तकनीकों में नेतृत्व करना होगा. उन्होंने आईटी उद्योग से शिक्षण संस्थानों के साथ मिलकर उद्योग की जरूरतों के अनुरूप पाठ्यक्रम तैयार करने और युवाओं को भविष्य के कोशल से लेस करने की अपील की. वैष्णव ने कहा कि सरकार देश की कंप्यूटिंग क्षमता बढ़ाने के लिए लगातार काम कर रही है.मंत्रो वैष्णव ने विकसित भारत 2047 का मंत्र भी दिया.

केंद्रीय मंत्री ने बताया कि देश का इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादन 13 लाख करोड़ रुपये के पार पहुंच चुका है और मोबाइल फोन भारत का सबसे बड़ा व्यक्तिगत निर्यात उत्पाद बन गया है. उन्होंने कहा कि ये उपलब्धियां भारत को वैश्विक तकनीकी और विनिर्माण केंद्र के रूप में तेजी से स्थापित कर रही हैं.

उन्होंने आईआईटी हैदराबाद में सेक्टर-विशिष्ट डेटा ट्रस्ट की पायलट परियोजना शुरू करने का भी सुझाव दिया, ताकि स्टार्टअप, शोधकर्ता और उद्योग सुरक्षित तरीके से भारतीय डेटा का उपयोग कर सकें.

पंजाब कांग्रेस में बढ़ी सियासी कलह!

चन्नी गुट ने राजा वडिंग को हटाने की उठाई मांग अब आलाकमान करेगा फैसला

चंडीगढ़, 11 जुलाई. पंजाब विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस की अंदरूनी खींचतान खुलकर सामने आ गई है. पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी के नेतृत्व वाले गुट ने पार्टी के पंजाब प्रभारी भूपेश बघेल के सामने प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वडिंग को हटाने की मांग रख दी है.

शनिवार को हुई अहम बैठक में चन्नी और उनके गुट के करीब 15 नेताओं ने एक स्वर में नेतृत्व परिवर्तन की पैरवी की. बैठक के दौरान चन्नी ने मौजूद नेताओं से हाथ उठाकर राय भी ली, जिसमें सभी ने कथित तौर पर राजा वडिंग

को प्रदेश अध्यक्ष पद से हटाने का समर्थन किया. नेताओं का कहना था कि पंजाब में कांग्रेस को मजबूत नेतृत्व की जरूरत है, जो सरकार के खिलाफ मजबूती से लड़ सके और कार्यकर्ताओं का भरोसा जीत सके. बैठक के बाद कांग्रेस सांसद सुखजिंदर सिंह रंधावा ने कहा कि कार्यकर्ताओं की भावनाओं से भूपेश बघेल को अवगत करा दिया गया है.

वहीं, भूपेश बघेल ने कहा कि सभी नेताओं ने खुलकर अपनी बात रखी है और जो भी सुझाव मिले हैं, उन्हें पार्टी आलाकमान के सामने रखा जाएगा. उन्होंने भरोसा दिलाया कि टिकट वितरण में केवल जीतने की क्षमता को

रिपोर्ट कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे और वरिष्ठ नेता राहुल गांधी को सौंपेगे, जिसके बाद नेतृत्व को लेकर अंतिम फैसला लिया जा सकता है. हालांकि कांग्रेस विधायक परगट सिंह ने पार्टी में किसी बड़े विवाद से इनकार करते हुए कहा कि सभी मतदाे बातचीत से सुलझा लिए जाएंगे और कांग्रेस एकजुट होकर चुनाव मैदान में उतरेगी. इसके बावजूद चुनाव से पहले पंजाब कांग्रेस में नेतृत्व को लेकर तेज हुई यह सियासी हलचल पार्टी के भीतर बढ़ती गुटबाजी की ओर साफ इशारा कर रही है.

प्राथमिकता दी जाएगी और सभी नेताओं के हितों का ध्यान रखा जाएगा.

हरियाणा में सरकारी सिस्टम की 24 घंटे होगी साइबर निगरानी

चंडीगढ़. हरियाणा सरकार डिजिटल शासन व्यवस्था को और अधिक सुरक्षित बनाने की दिशा में तेजी से काम कर रही है. मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी द्वारा वर्ष 2026-27 के बजट में घोषित 'हरियाणा डिजिटल कवच' पहल के तहत व्यापक साइबर सुरक्षा तंत्र विकसित किया जा रहा है. इसी उद्देश्य से सूचना प्रौद्योगिकी, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं संचार विभाग ने भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सहयोग से चंडीगढ़ में राज्य स्तरीय परामर्श कार्यशाला आयोजित की. कार्यशाला में डीआईटीसी के निदेशक समवर्तक सिंह खगवाल ने कहा कि साइबर सुरक्षा अब केवल तकनीकी आवश्यकता नहीं बल्कि सुरक्षासन, जनविश्वास और प्रभावी सेवा वितरण का आधार बन चुकी है. आधिकारिक जानकारी के अनुसार हरियाणा डिजिटल कवच के तहत सभी सरकारी विभागों के लिए 24 घंटे साइबर निगरानी, संभावित खतरों की पहचान, त्वरित घटना प्रतिक्रिया, अनिवार्य सुरक्षा मानकों का पालन और नियमित सुरक्षा ऑडिट की व्यवस्था की जा रही है. इससे सरकारी नेटवर्क और नागरिकों के डिजिटल डेटा की सुरक्षा और संजवत होगी. कार्यशाला में भ्रमते साइबर खतरे, डेटा प्रबंधन, डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण (डीपीडीपी), साइबर अपराध रोकथाम, सरकारी संस्थानों की साइबर सुरक्षा, विद्युत क्षेत्र के डिजिटल ढांचे की सुरक्षा और सुरक्षित एआई आधारित आईटी प्रणाली जैसे विषयों पर विस्तृत चर्चा हुई. इसमें राज्य सरकार के विभिन्न विभागों, हरियाणा पुलिस, विद्युत विभाग तथा निजी क्षेत्र के साइबर सुरक्षा विशेषज्ञों ने भाग लिया।